



आइटीओ बस पड़ाव से मुफ्त वाईफाई की शुरुआत

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 19 दिसंबर।

अब दिल्ली वाले मुफ्त वाईफाई सेवा का प्रयोग कर सकेंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आइटीओ बस स्टॉप से मुफ्त वाईफाई सेवा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने इस सेवा के जरिए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली दुनिया का पहला शहर है जहां पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। आइटीओ से दिल्ली सरकार ने 109 हॉटस्पॉट की शुरुआत की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से दिल्ली को मार्डन वर्ल्ड क्लास शहर बनाने में मदद मिलेगी। देर शाम तक सभी 109 हॉटस्पॉट चालू कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली के विभिन्न इलाकों में 500 हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे। सरकार की योजना के मुताबिक आने वाले छह माह में 11 हजार हॉटस्पॉट लगाने का कार्य खत्म किया जाएगा। सरकार की योजना के मुताबिक आम जनता को हर 500 मीटर दूरी पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध होगी। एक अनुमान के मुताबिक 11 हजार हॉटस्पॉट लग जाने के बाद एक समय में 22 लाख लोग एक साथ मुफ्त वाईफाई का इस्तेमाल कर सकेंगे। दिल्ली सरकार एक उपभोक्ता को प्रतिमाह 15 जीबी डाटा मुफ्त देगी।

सरकार की योजना के मुताबिक दिल्ली के चार हजार बस स्टॉप पर वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सात हजार अन्य जगहों को भी इस सेवा के लिए चिह्नित किया गया है। इनमें स्थानीय नागरिक संगठन, बाजार व अन्य स्थान हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें खुशी है कि शायद भारत के इतिहास में यह पहली सरकार होगी, जिसने चुनाव में जितने वादे किए थे, उन सभी को पूरा

- दिल्ली में एक साथ शुरू हुए 109 हॉटस्पॉट
- हर सप्ताह 500 हॉटस्पॉट लगाने की तैयारी
- 6 माह में लगभग 11 हजार हॉटस्पॉट

किया है। यह आखिरी वादा था, इसे भी दिल्ली सरकार ने पूरा किया है।

रेंज बदलने पर भी नहीं टूटेगा वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन



एक हॉटस्पॉट पर 150 से 200 लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम औसतन 200 यूजर मानें और 11 हजार हॉटस्पॉट्स मानें तो 22 लाख उपभोक्ता एक साथ इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे।

हॉटस्पॉट्स को आसानी से इस्तेमाल करने के लिए एक ऐप बनाया गया है। इस ऐप को जारी कर दिया जाएगा। उस ऐप के जरिए उपभोक्ता को अपनी केवाईसी का विवरण भरना होगा। केवाईसी भरने के बाद उपभोक्ता के फोन में ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद इंटरनेट का कनेक्शन चालू हो जाएगा।

एक सप्ताह तक अपने हॉटस्पॉट्स के जोन से निकल कर दूसरे के जोन में जाते हैं, तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं होगा, बल्कि दूसरे हॉटस्पॉट्स में जाकर कनेक्ट हो जाएगा। पहले फेज में 11 हजार हॉटस्पॉट्स लगाए जा रहे हैं।

यहां से होगी मुफ्त वाईफाई सुविधा की शुरुआत

- कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन
- कश्मीरी गेट आइएसबीटी
- आइटीओ बस स्टैंड
- मंडी हाउस बस स्टैंड
- दिल्ली सचिवालय
- इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन
- दिल्ली विश्वविद्यालय बस स्टैंड
- सराय काले खां बस स्टैंड

भविष्य में सीसीटीवी कैमरों से भी जोड़े जाएंगे हॉटस्पॉट

दिल्ली में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी भविष्य में मुफ्त वाईफाई सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे दिल्ली को और सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। दिल्ली में लगे सीसीटीवी कैमरों व वाईफाई का रखरखाव दिल्ली सरकार ही करेगी। इस पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

इण्डियन ओवरसीज बैंक असेट रिकवरी मैनेजमेंट शाखा

रचना बिल्डिंग, वतुर्थ तल, 2, राजेंद्रा प्लेस, पूसा रोड, नई दिल्ली -110008, फोन न. 011-25758124, ई मेल : iob1997@iob.in शुद्ध पत्र यह 10.12.2019 को फाइनेंसियल एक्सप्रेस और जनसत्ता में प्रकाशित सूचना के संदर्भ में है, जिसमें दो सुधार निम्नानुसार है: 1. खाता महावीर मेडीवेल सौरियल नंबर 6 के खाते में बैंकिंग के सम्पन्न के लिए अस्थायी दिनांक और समय 12.12.2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे के बजाय 26.12.2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे का समय निर्धारित है। 2. अबल संपत्ति का विवरण: प्रथम तल, बी-77, दयानंद कॉलोनी, लाजपत नगर- IV, नई दिल्ली -110024 के बजाय, प्रथम तल, बी-77 एम, दयानंद कॉलोनी, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली -110024 पढ़ा जाये। अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक तिथि : 10.12.2019

PUBLIC ANNOUNCEMENT

Regulation 31(2) read with Regulation 12(3) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF ASSOCIATED TRADE LOGISTICS PRIVATE LIMITED - IN LIQUIDATION Pursuant to Regulation 31 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 ("Regulations"), Public Announcement is hereby made to all the Stakeholders of the Company that the List of Stakeholders of the Company has been filed with Hon'ble NCLT, New Delhi Bench III, on December 19, 2019. As there is no functional website of the Corporate Debtor, hence the List of Stakeholders showing complete details of the amount of claims admitted by the Liquidator, including modified amount from time to time, extent up to which the claims are secured/unsecured, details of Stakeholders and proofs admitted/rejected in part and those wholly rejected, if any, can be viewed on the website of the Liquidator, on the following link: https://www.ilcgrp.com/associated-trade-logistics-pvt-ltd/ The Stakeholders are further notified that any modification of entry in the List of Stakeholders, as filed with the Hon'ble NCLT, New Delhi Bench III can be made only by filing an application with the Hon'ble NCLT, New Delhi Bench III and in the manner directed by the Bench. Sd/- Shalu Khanna (Liquidator) M/s. Associated Trade Logistics Pvt. Ltd. - In Liquidation IBBI Regn. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00917/2017-2018/11523 Address: Luthra & Luthra Restructuring and Insolvency Advisors LLP A-16/9, Vasant Vihar, New Delhi-110 057, India. Email: atl-pr@ilca.net Date: 19th December, 2019 Place: New Delhi

HDFC हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनैस कॉर्पोरेशन लि.

उत्तरी क्षेत्र कार्यालय : द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली-110 067 दूरभाष: 011-41115111, कॉर्पोरेट पहचान संख्या: L70100MH1977PLC019916, वेबसाइट: www.hdfc.com

कच्चा सूचना सूची, हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारियों ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अधीन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन निम्नलिखित कर्जदारों/गारंटर्स/कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों को एक मांग सूचना जारी की जिसमें उनके नामों के सम्मुख दर्शाई गई राशि और कथित सूचना में दर्शाये गए विवरण के अनुसार लागू दर पर ब्याज तथा भुगतान की तिथि और/या वसूली तक प्रासंगिक व्यय, लागत एवं प्रभार आदि के साथ राशि को कथित मांग सूचना(ओं) की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया।

क्र. सं.	कर्जदारों/गारंटर्स/कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों का नाम/ऋण खाता संख्या	बकाया राशि	मांग सूचना की तिथि	कच्चा करने की तिथि	अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण
1.	श्री फहीम अली एवं श्रीमती हसन फारिमा (कर्जदार) ऋण खाता सं. 622635250	31 जुलाई, 2019* को बकाया रु. 27,78,170/-, (केवल सप्ताहस 1 लाख अठसत्तर हजार एक सौ सत्तर रुपए)	03 सितम्बर, 2019	17 दिसम्बर 2019 (भौतिक)	गांव नूरनगर, राज नगर परगना लोनी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के खसरा नं. 1010, 1011 और 1012 पर स्थित प्लेट नं. ई-501, ब्लॉक-ई, चौधी मंजिल, एससीसी सैफायर निचली भूमि पर अधिभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ।
2.	श्रीमती पूरम प्रियदर्शनी सिंह एवं श्री संजय जोशी (कर्जदार) ऋण खाता सं. 617077920	31 जुलाई, 2019* को बकाया रु. 53,88,465/-, (केवल तिरपन लाख अठारसी हजार चार सौ पैंसठ रुपए)	03 सितम्बर, 2019	18 दिसम्बर 2019 (भौतिक)	प्लेट नं. बी1/1459, 14वीं मंजिल, टॉवर 12 ए, पूर्वोत्तर रायल सिटी, प्लॉट नं. जीएच-05, सेक्टर सोएचआई-ट, गेट नोएडा, उत्तर प्रदेश निचली भूमि पर अधिभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ।
3.	श्री शैलेन्द्र कुमार (कर्जदार) ऋण खाता सं. 604865988	31 जुलाई, 2019* को बकाया रु. 29,50,706/-, (केवल उन्तीस लाख पचास हजार सात सौ छह रुपए)	03 सितम्बर, 2019	17 दिसम्बर 2019 (प्रतीकात्मक)	प्लेट नं. 1203, 12वीं मंजिल, टॉवर एसके-3, देविका रिकपर्स, खसरा नं. 1148, नूर नगर, परगना लोनी, राज नगर एक्सटेंशन, एनएच-58, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश और उस पर वर्तमान एवं भविष्य में निर्माण।
4.	श्री दीपक चौधरी एवं सुश्री कमलेश देवी (कर्जदार) ऋण खाता सं. 626788476 और 625397155	30 जून, 2019* को बकाया रु. 8,16,910/-, (केवल आठ लाख सोलह हजार नौ सौ दस रुपए)	22 जुलाई, 2019	17 दिसम्बर 2019 (प्रतीकात्मक)	प्लेट नं. ए-3252, तीसरी मंजिल, टॉवर नं.-35, ब्लॉक नं. 35, दिनेश नगर, एनएच-24, पबलामोदी नगर रोड, पिखुवा, गाजियाबाद निचली भूमि पर अधिभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ।
5.	श्री पंकज कुमार पाण्डे एवं श्रीमती प्रियंका पाण्डे (कर्जदार) श्री रविन्द्र कुमार (गारंटर) ऋण खाता सं. 601663729	30 जून, 2018* को बकाया रु. 13,36,021/-, (केवल तेरह लाख छत्तीस हजार इककीस रुपए)	13 अगस्त, 2018	18 दिसम्बर 2019 (प्रतीकात्मक)	सूजीएफ-डी, एलआईडी, भासिन अपार्टमेंट-2, प्लॉट नं. 1/433, निति खण्ड-1, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश और उस पर वर्तमान एवं भविष्य में निर्माण।

*भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज, आकरिमिक व्यय, लागत, शुल्क आदि के रूप में आगे ब्याज के साथ। तथापि, उपरोक्त वर्णित कर्जदार/गारंटर बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहें। विशेषतः उपरोक्त वर्णित कर्जदारों/गारंटर्स/कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों और आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि एचडीएफसी लि. के प्राधिकृत अधिकारियों ने अधिनियम की धारा 13(4) के पठित अधिनियम के नियम 8 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित क्र.सं. 1 और 2 की अचल परिसम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों पर भौतिक कच्चा तथा उपरोक्त वर्णित क्र.सं. 3, 4 और 5 की अचल परिसम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों पर प्रतीकात्मक कच्चा ले लिया है।

विशेषतः उपरोक्त वर्णित कर्जदारों/गारंटर्स/कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों और आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दर्शाई गई अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का किसी भी तरह से लेनदेन न करें और कथित अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का कोई भी लेनदेन हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनैस कॉर्पोरेशन लि. के अधीन होगा। प्रतिभूत संपत्ति (संपत्तियां) वापस लेने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में कर्जदारों/गारंटर्स/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों का ध्यान कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

तैयार पंचनामा और बनाई गई इन्चेंट्री की प्रतियां अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं। कथित कर्जदारों/गारंटर्स/कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों से आग्रह है कि संबंधित प्रति अधोहस्ताक्षरी से किसी कार्य दिवस में सामान्य कार्य अवधि में प्राप्त कर लें।

कृते हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनैस कॉर्पोरेशन लि. ह0/- दिनांक: 19.12.2019 प्राधिकृत अधिकारी

पंजीकृत कार्यालय: रेमन हाउस, एच.टी. पारेख मार्ग, 169, बैकबे रीक्लेमेशन, चर्चंगेट, मुंबई-400 020

प्रपत्र एच सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय विद्याला और ऋण शोध अकादमी बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अकादमी समाधान प्रक्रिया) विनियमनवली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

साडी इस्पात लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ संबंधित विवरण

क्र. सं.	कार्पोरेट लेनदार का नाम	साडी इस्पात लिमिटेड
1.	कार्पोरेट लेनदार के निम्नलिखित की तिथि	03/06/1970
2.	कार्पोरेट लेनदार के निम्नलिखित की तिथि	03/06/1970
3.	कार्पोरेट लेनदार के निम्नलिखित की तिथि	03/06/1970
4.	कार्पोरेट लेनदार के निम्नलिखित की तिथि	03/06/1970
5.	कार्पोरेट लेनदार के निम्नलिखित की तिथि	03/06/1970
6.	कार्पोरेट लेनदार के निम्नलिखित की तिथि	03/06/1970
7.	कार्पोरेट लेनदार के निम्नलिखित की तिथि	03/06/1970
8.	कार्पोरेट लेनदार के निम्नलिखित की तिथि	03/06/1970
9.	कार्पोरेट लेनदार के निम्नलिखित की तिथि	03/06/1970
10.	कार्पोरेट लेनदार के निम्नलिखित की तिथि	03/06/1970
11.	कार्पोरेट लेनदार के निम्नलिखित की तिथि	03/06/1970
12.	कार्पोरेट लेनदार के निम्नलिखित की तिथि	03/06/1970
13.	कार्पोरेट लेनदार के निम्नलिखित की तिथि	03/06/1970
14.	कार्पोरेट लेनदार के निम्नलिखित की तिथि	03/06/1970

प्रपत्र एच सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय विद्याला और ऋण शोध अकादमी बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अकादमी समाधान प्रक्रिया) विनियमनवली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

मैसर्स डी सी होम्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ संबंधित विवरण

क्र. सं.	कार्पोरेट लेनदार का नाम	मैसर्स डी सी होम्स प्राइवेट लिमिटेड
1.	कार्पोरेट लेनदार के निम्नलिखित की तिथि	06.01.2011
2.	कार्पोरेट लेनदार के निम्नलिखित की तिथि	06.01.2011
3.	कार्पोरेट लेनदार के निम्नलिखित की तिथि	06.01.2011
4.	कार्पोरेट लेनदार के निम्नलिखित की तिथि	06.01.2011
5.	कार्पोरेट लेनदार के निम्नलिखित की तिथि	06.01.2011
6.	कार्पोरेट लेनदार के निम्नलिखित की तिथि	06.01.2011
7.	कार्पोरेट लेनदार के निम्नलिखित की तिथि	06.01.2011
8.	कार्पोरेट लेनदार के निम्नलिखित की तिथि	06.01.2011
9.	कार्पोरेट लेनदार के निम्नलिखित की तिथि	06.01.2011
10.	कार्पोरेट लेनदार के निम्नलिखित की तिथि	06.01.2011
11.	कार्पोरेट लेनदार के निम्नलिखित की तिथि	06.01.2011
12.	कार्पोरेट लेनदार के निम्नलिखित की तिथि	06.01.2011
13.	कार्पोरेट लेनदार के निम्नलिखित की तिथि	06.01.2011
14.	कार्पोरेट लेनदार के निम्नलिखित की तिथि	06.01.2011

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिनियम के विनियम 68 दिनांक 2019 को मैसर्स डी सी होम्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अकादमी प्रक्रिया अर्थ करने का आदेश दिया है। [अर्जदारी को आदेश 19.12.2019 को प्राप्त हुए]

मैसर्स डी सी होम्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 02 जनवरी 2020 को अपना पूर्ण अंतिम समाधान प्रोसेसल के रूप में प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

किसी भी के साथ सम्बन्धित लिखित लेनदारों के नाम कि प्रतियां सं. 12 के संख्या सूचीबद्ध हैं, अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत सं. 13 के संख्या सूचीबद्ध हैं। ऋण शोध अकादमी प्रोसेसल में से अपनी परदे का अधिकृत प्रतिनिधि को प्राप्त और (अथवा) के निर्देशित करण-अनुमति नहीं।

दावे के पूर्ण अंतिम प्रमाण की प्रतियां दर्शनीय होगी। हस्ता/— राज कुमार गुप्ता, अंतिम समाधान प्रोसेसल पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00064/2017-18/10142



I choose substance over sensation.

Inform your opinion with credible journalism.

The Indian Express. For the Indian Intelligent.

The Indian EXPRESS JOURNALISM OF COURAGE